

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठारीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०ए०))

वाद सं० : 803 सन 2020

अनवान :-

1. नागर पुत्र इन्दु जाति मनियारा साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 25/01/2022

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया की रोही मौजा ननाउ के खसरा नम्बर 736/1 की 11.01 बीघा भूमि दिनांक 1.12.1975 को नागर पुत्र इन्दु जाति मनियारा तहसील नोहर को आवंटित की गई थी आवंटन से लेकर आवंटन की गई भूमि आवंटी नागर पुत्र इन्दु जाति मनियारा के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वाद भूमि नागर पुत्र इन्दु को आवंटित भूमि है जो आवंटी नागर पुत्र इन्दु के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है आवंटी के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

उक्त भूमि आवंटी नागर पुत्र इन्दु को आवंटन होने से लेकर आज तक आवंटी नागर पुत्र इन्दु के कब्जा काश्त में रही आवंटी द्वारा आवंटन की समस्त शर्तों की पालना की जा रही है वाद भूमि आवंटन होने के 10 वर्षों बाद स्वत ही खातेदार काश्तकार हो गया था किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है जिससे वादी के खातेदार अधिकारों का हनन होता है वादी आवंटित भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी वाद भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है इसलिये वाद भूमि वादी को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे किन्तु इन्कार हो गये इसलिये वादी ने अपने हकों की धोषणा करवाने के लिये वाद पेश किया गया है।


अतः वादी का वाद डिफ्री किया जाकर रोही मौजा ननाउ के खसरा नम्बर 736/1 की 11.01 बीघा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित आकर वादी के वाद के समन्ध में जबाब पेश किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है उपनिवेशन क्षेत्र में आने वाली भूमि के खातेदारी अधिकार उपनिवेशन नियमों के तहत ही पाने का अधिकारी है एवं राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। परोकार राज का जबाब पेश होने पर शामिल मिराल किया जाकर वादी से साक्ष्य लिये गये वादी ने साक्ष्यवादी में अपना शपथपत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की रोही मौजा ननाउ के खसरा नम्बर 736/1 की 11.01 बीघा भूमि दिनांक 1.12.1975 को नागर पुत्र इन्दु जाति मनियारा तहसील नोहर को आवंटित की गई थी आवंटन से लेकर आवंटन की गई भूमि आवंटी नागर पुत्र इन्दु जाति मनियारा के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वाद भूमि नागर पुत्र इन्दु को आवंटित भूमि है जो आवंटी नागर पुत्र इन्दु के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है आवंटी के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

उक्त भूमि आवंटी नागर पुत्र इन्दु को आवंटन होने से लेकर आज तक आवंटी नागर पुत्र इन्दु के कब्जा काश्त में रही आवंटी आवंटन की समस्त शर्तों की पालना की जा रही है वाद भूमि आवंटन होने के 10 वर्षों बाद स्वत ही खातेदार काश्तकार हो गया था किन्तु


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है जिससे वादी के खातेदार अधिकारों का हनन होता है वादी को आवंटित भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ जाने के कारण यदि उपनिवेशन नियमों के तहत भी वाद भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जाकर वादी के हकों की घोषणा की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वाद भूमि राही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ चुकी है इसलिये वाद भूमि के खातेदारी अधिकार उपनिवेशन नियमों/परिपत्रों के अधीन ही वादी पाने का अधिकारी है एवं राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ननाउ के खसरा नम्बर 736/1 की 11.01 बीघा भूमि नागर पुत्र इन्दु को दिनांक 01.12.1975 को आवंटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश /नामान्तकरण से साबित है।

वादी को आवंटी भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 689/677 की कुल 2.7950 है बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसके सम्बन्ध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी आवंटी नागर पुत्र इन्दु को वाद भूमि दिनांक 12.01.1975 को आवंटित की गई थी जो आवंटी नागर पुत्र इन्दु के कब्जा काश्त में चली आ रही है। जो प्रस्तुत गिरदावारीयों/तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि आवंटन के समय से वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है पर किसी प्रकार का ऐतराज नहीं किया गया अर्थात् वाद भूमि आवंटन से लेकर आज तक आवंटी नागर पुत्र इन्दु के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसे दिनांक 01.12.1975 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तों के अनुसार वादी दिनांक 01.12.1975 के सात वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिससे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी को बरानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते हैं।

पेरोकार राज का कथन उचित प्रतीत होता है वाद भूमि वादी को बरानी क्षेत्र में आवंटन की गई थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ चुकी है उपनिवेशन नियमों के तहत ही खातेदार पाने के अधिकारी है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमियां जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई हैं के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में समय समय पर परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई हैं वादी उन्हीं के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है जिसके लिये वादी सहमत भी है।

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदारी अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (2) col/2005 जयपुर दिनांक 28.05.2007 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमों के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदारी अधिकारों के लिए अनु० जाति अनु० जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व बीपीएल परिवारों से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त बसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। अधिसूचना दिनांक 28.05.2007 निम्नानुसार है :-

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been


उपनिवेशन अधिकारी,
नोहर

allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प-4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते हैं। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

इस प्रकार राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 28.05.2007 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं।


वादी नागर पुत्र इन्दु को रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 689/677 के खसरा न0 736/5 की कुल 2.7950हैक भूमि दिनांक 01.12.1975 को आवंटन की गई थी नागर पुत्र इन्दु के नाम वर्तमान में गैरखातेदार दर्ज है जो आवंटन नियम 1957 के तहत भूमि आवंटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है।

पेरोकार राज के अनुसार वाद भूमि वादी /आवंटी के कब्जा काश्त में आदिनांक तक चली आ रही है किराी प्रकार का स्थगन आदेश विवाद नहीं है नगर पालिका पेराफेरी में नहीं है ना ही विशेष आवंटन की सूची में शामिल है वादी /आवंटी के पास वाद भूमि को मिलाने पर सीलिंग सीमा से कम भूमि है वादी /आवंटी अन्य पिछडा वर्ग (लखारा) जाति का सदस्य है एवं वाद भूमि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आती है एवं वादी को पुखा आवंटन की अभिशथा की गई है।

वादी /आवंटी को आवंटन की गई भूमि पर तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के अनुसार किया प्रकार का विवाद एवं पुखा आवंटन की अभिशथा एवं आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसूचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं परिपत्रों के अधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 689/677 के खसरा न0 736/5 की कुल 2.7950हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/- प्रतिबीघा का 20 प्रतिशत 400/-प्रतिबीघा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के पर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिराल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तर्तीय तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हुंगुमिगिण्ड)
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अवजलत :- सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. नागर पुत्र इन्दु जाति मनियारा साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।


प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 803 सन 2020 निर्णय दिनांक - 25/01/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मीजा ननाउ के खाता संख्या 689/677 के खसरा नं० 736/5 की कुल 27950 हैक्ठु भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/- प्रतिहीघा का 20 प्रतिशत 400/- प्रतिहीघा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के पर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)